BYJU'S EXAM PREP

Weekly Current Affair

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

(06-12 March 2022)

Weekly Current Affairs

Table of Contents

International Relations .....

National.....

State.....

Economy.....

Polity.....

Defense.....

Appointments/Resignations.....

Awards & Honours.....

Important Days.....

Science & Technology.....

Environment.....

Sports.....

Books & Authors.....

Schemes in News.....

Obituaries.....

Ranks and Indices.....

Miscellaneous.....

International Relations

बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA)

चर्चा में क्यों?

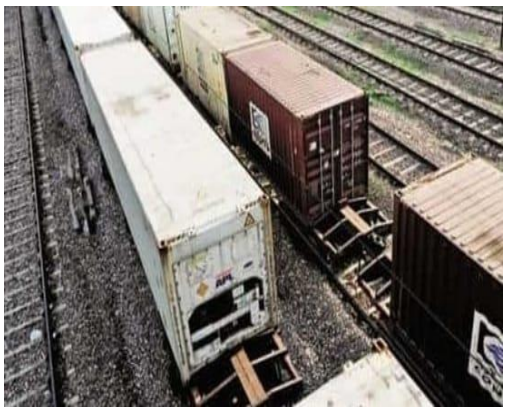

- भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने लंबे समय से चले आ रहे **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA)** को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप दिया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) द्वारा वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौते पर सहमत होने में विफल रहने के बाद BBIN कनेक्टिविटी परियोजना की कल्पना की गई थी।
- BBIN परियोजना को वर्ष 2017 में तब झटका लगा जब MVA के लिये संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण भूटान ने अस्थायी रूप से इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना।
- 3 अन्य देशों ने उस समय समझौते के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।

इसी तरह की कनेक्टिविटी पहल जिसका भारत हिस्सा है:

- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग
- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट (KMMTT)
- बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (BCIM) कॉरिडोर

स्रोत: HT

डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

- स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी-डेम संस्थान की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर एक औसत नागरिक के पास मौजूद लोकतंत्र का स्तर वर्ष 1989 के स्तर से नीचे चला गया है और साथ ही शीत युद्ध के बाद की अवधि के दौरान प्राप्त लोकतांत्रिक लाभ तेज़ी से घट रहे हैं।

- इस अध्ययन का शीर्षक 'डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022: ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर?' है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स (LDI) में उनके स्कोर के आधार पर देशों को चार शासन प्रकारों में वर्गीकृत करती है: लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **स्वीडन** LDI सूचकांक में सबसे ऊपर है, अन्य स्कैंडिनेवियाई देश जैसे डेनमार्क और नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड के साथ उदार लोकतंत्र रैंकिंग में शीर्ष पांच में हैं।
- निरंकुशता का तेज़ी से प्रसार हो रहा है तथा 33 देशों में निरंकुशता की स्थिति दर्ज की गई है।

भारत का प्रदर्शन:

- भारत बहुलता-विरोधी राजनीतिक दल की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसने निरंकुश शासन को आगे बढ़ाया है।
- LDI में भारत 93वें स्थान पर था, और इसे "निचले 50%" देशों में शामिल किया गया है।
- इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इसका प्रदर्शन और अधिक खराब हुआ है तथा यह 100वें स्थान पर पहुँच गया है, इसके अलावा डेलिवरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में यह 102वें स्थान पर है।
- दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो LDI में भारत का स्थान श्रीलंका (88), नेपाल (71) और भूटान (65) से नीचे तथा पाकिस्तान (117) से ऊपर है।

नोट: इससे पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस द्वारा ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021 जारी की गई थी।

स्रोत: द हिंदू

मानवीय गलियारे

चर्चा में क्यों?

- रूस ने नागरिकों के लिए **मानवीय गलियारों** की अनुमति देने के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध में आंशिक युद्धविराम की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

मानवीय गलियारे:

- संयुक्त राष्ट्र मानवीय गलियारों को सशस्त्र संघर्ष के अस्थायी विराम के कई संभावित रूपों में से एक मानता है।
- उदाहरण के लिये नागरिकों को लक्ष्य बनाते हुए बड़े पैमाने पर बमबारी के समय मानवीय गलियारे महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकते हैं।
- ये एक विशिष्ट क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय के लिये विसैन्यीकृत क्षेत्र होते हैं जिस पर एक सशस्त्र संघर्ष के दोनों पक्ष सहमत होते हैं।
- इन गलियारों के माध्यम से संघर्ष के क्षेत्रों में भोजन एवं चिकित्सा जैसी सहायता प्रदान की जा सकती है या नागरिकों को निकाला जा सकता है।
- ज्यादातर मामलों में, मानवीय गलियारों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बातचीत की जाती है। कभी-कभी वे स्थानीय समूहों द्वारा भी स्थापित किए जाते हैं।
- 1990 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के प्रस्ताव 45/100 में मानवीय गलियारों को परिभाषित किया गया था।
- मानवीय गलियारों तक पहुंच संघर्ष के पक्षों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह आमतौर पर तटस्थ अभिनेताओं, संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस जैसे सहायता संगठनों तक सीमित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री मोदी ने क्वॉड के शीर्ष नेतृत्व की वर्चुअल शिखर-वार्ता में हिस्सा लिया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा के साथ क्वॉड के शीर्ष नेतृत्व की वर्चुअल शिखर-वार्ता में हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस शिखर-वार्ता में सितंबर 2021 को आहूत क्वॉड शिखर-वार्ता के बाद क्वॉड की पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई।
- सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इस वर्ष के अंत में जापान में होने वाली शिखर-वार्ता के आयोजन तक ठोस नतीजे प्राप्त करने के उद्देश्य से सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मानवीय और आपदा राहत, ऋण वहनीयता, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, संपर्कता और क्षमता-निर्माण जैसे क्षेत्रों में क्वॉड में आंतरिक सहयोग के ठोस तथा व्यावहारिक स्वरूप का आह्वान किया।
- उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन तथा सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के महत्त्व को दोहराया।
- सभी राष्ट्राध्यक्षों ने अन्य मुख्य विषयों पर भी चर्चा की, जिनमें दक्षिण-पूर्व एशिया, हिन्द महासागर क्षेत्र और प्रशांत द्वीपसमूह की परिस्थिति शामिल थी।

क्वाड के बारे में:

- क्वाड, या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, चार देशों - ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अनौपचारिक समूह है।
- इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करना है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसने हाल के वर्षों में चीनी सैन्य मुखरता में वृद्धि देखी है।
- क्वाड का पहला इन-पर्सन समिट सितंबर 2021 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा

चर्चा में क्यों?

- **फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)** ने एक बार फिर पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी सूची में बनाए रखा है, जिसे "ग्रे लिस्ट" के रूप में भी जाना जाता है और देश को "जटिल मनी लॉन्ड्रिंग जांच और अभियोजन पर काम करने के लिए कहा है।

प्रमुख बिंदु

- जून 2018 से पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और धन शोधन रोधी व्यवस्थाओं में कमियों के लिए FATF की ग्रे सूची में है।
- इस ग्रेलिस्टिंग ने इसके आयात, निर्यात, प्रेषण और अंतरराष्ट्रीय उधार तक सीमित पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के बारे में तथ्य:

- FATF एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना G7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए की गई है। 2001 में, आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए इसके जनादेश का विस्तार किया गया था।

- **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस

- **स्थापना:** 1989

- **सदस्यता:** 39

FATF की दो लिस्ट:

- **ग्रे लिस्ट:** वे देश जिन्हें आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। 'बढ़ी हुई निगरानी सूची' 'ग्रे लिस्ट' का दूसरा नाम है।

- **ब्लैक लिस्ट:** जिन देशों को असहयोगी देश कहा जाता है, उन्हें काली सूची में डाल दिया जाता है। ये देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।

स्रोत: HT

National

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री SVAMITVA योजना के तहत सांसदों / विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में ड्रोन उड़ान शुरू होने के बारे में सूचित करने के लिए SMS भेजने की कार्यक्षमता शुरू करेंगे

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह विकसित नई कार्यक्षमता का शुभारंभ करेंगे, जिसमें **SVAMITVA योजना** के तहत सर्वेक्षण के लिए निर्धारित अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ड्रोन उड़ान शुरू होने के बारे में सूचित करने वाले सांसदों और विधायकों को SMS किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री 11 मार्च 2022 को पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA), भारतीय सर्वेक्षण (SoI), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्षमता का शुभारंभ करेंगे।
- यह नई कार्यक्षमता योजना की व्यापक पहुंच और पारदर्शिता में मदद करेगी।

SVAMITVA योजना के बारे में:

- SVAMITVA (स्वामित्व), पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में गांव के घर के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है।
- यह योजना पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से पांच वर्षों (2020-2025) की अवधि में लागू की जा रही है और अंततः 2025 तक देश भर के सभी गांवों को कवर कर देगी।
- योजना देश भर में योजना को पूरा करने की अपनी यात्रा में एक अलग मील का पत्थर हासिल कर रही है, अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 108 जिलों में ड्रोन उड़ान भरी जा चुकी है और कई और पूरा होने के कगार पर हैं।

स्रोत: PIB

भारत को मानेसर में पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर प्राप्त हुआ

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय विद्युत मंत्री, आर के सिंह ने **वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (SGKC)** और इनोवेशन पार्क को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- मानेसर (हरियाणा) में पावरग्रिड केंद्र के भीतर स्थित नया वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, केंद्र सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है।
- SGKC को पावरग्रिड द्वारा फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और उन्नति के लिए स्थापित किया गया है।
- यह US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है।
- SGKC का लक्ष्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में इनोवेशन, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना और बिजली वितरण क्षेत्र में क्षमता विस्तार के लिए विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक बनना है।

अन्य संबंधित पहलें:

- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (SMNP)
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)

स्रोत: ET

'MSME इनोवेटिव स्कीम (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और IPR)' और ' MSME आइडिया हैकथॉन 2022'

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री नारायण राणे ने **MSME आइडिया हैकथॉन 2022** के साथ **MSME इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और IPR)** का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- MSME इनोवेशन योजना इस क्षेत्र की उस रचनात्मकता को बढ़ावा देगी जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।
- यह इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगा और अच्छे बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए मार्गदर्शन भी देगा। ऐसे आइडिया आगे चलकर समाज को सीधे लाभ प्रदान करेंगे।
- MSME इनोवेटिव MSME के लिए एक नई अवधारणा है जहां इन्क्यूबेशन में इनोवेशन, डिजाइन इंटरवेंशन और सिंगल मोड एप्रोच में इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) की रक्षा के लिए काम किया जाएगा। भारत के इनोवेशन के बारे में MSME के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें MSME चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करने पर भी इसका जोर रहेगा।

उप-योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :-

- **इनक्यूबेशन**
- डिजाइन
- IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार)

स्रोत: PIB

भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरू किया गया

चर्चा में क्यों?

- **'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल' (GCT)** के संबंध में प्रधानमंत्री के विजन "गति शक्ति" और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप भारतीय रेल के आसनसोल मंडल (डिवीजन) ने **थापरनगर** में **मैथन** पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है।
- **दिसंबर '2021 में GCT नीति के सामने आने के बाद से यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला GCT है।**

प्रमुख बिंदु

- मैथन विद्युत परियोजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी और 2011 में यहां विद्युत का उत्पादन शुरू किया गया था।
- अब तक इस विद्युत परियोजना के लिए कोयले की जरूरत सड़क के रास्ते पूरी की जा रही थी। लेकिन अब हर महीने 120 इनवार्ड (आने वाला) कोयला रैक से इसकी जरूरत पूरी की जाएगी।
- वहीं, फ्लाई ऐश के 2 से 4 आउटवार्ड (जाने वाला) रेकों को साइडिंग से भेजे जाने का अनुमान है।
- इससे रेलवे की कमाई में हर महीने लगभग 11 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी।

स्रोत: PIB

संस्कृति राज्य मंत्री ने साहित्योत्सव का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

- भारत का संयुक्त साहित्य उत्सव, साहित्य अकादमी का फेस्टिवल ऑफ लैटर्स, **साहित्योत्सव** नई दिल्ली में शुरू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2022 भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है।
- महोत्सव की शुरुआत संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा अकादमी की प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई।
- प्रदर्शनी में पिछले वर्ष आयोजित अकादमी की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- साहित्योत्सव के दौरान प्रतिष्ठित **साहित्य अकादमी पुरस्कार** 24 पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे।

स्रोत: PIB

शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की

चर्चा में क्यों?

- शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर **यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) प्लस (UDISE+) 2020-21** पर रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

- विद्यालयों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की UDISE+ प्रणाली को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य दस्तावेज के प्रारूप में मैनुअल डेटा भरने के पहले के अभ्यास और इसके बाद 2012-13 से संचालित UDISE डेटा संग्रह प्रणाली में प्रखंड या जिला स्तर पर कंप्यूटर पर फीडिंग से संबंधित मुद्दों को दूर करना है।
- UDISE+ डेटा से संबंधित मौजूदा रिपोर्ट साल 2020-21 के लिए संदर्भित है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- 2020-21 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में **नामांकित कुल छात्रों** की संख्या 25.38 करोड़ थी। इससे पहले 2019-20 में यह आंकड़ा 25.10 करोड़ था। यानी 2020-21 में नामांकन में 28.32 लाख की बढ़ोतरी हुई है।
- **सकल नामांकन अनुपात (GER),** जो भागीदारी के सामान्य स्तर का मापन करता है, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान सुधार हुआ है। 2019-

20 की तुलना में 2020-21 में स्तरवार GER हैं: उच्च प्राथमिक में 89.7 फीसदी से 92.2 फीसदी, प्राथमिक में 97.8 फीसदी से 99.1 फीसदी, माध्यमिक में 77.9 फीसदी से 79.8 फीसदी और उच्चतर माध्यमिक में 51.4 फीसदी से 53.8 फीसदी।

- 2020-21 के दौरान विद्यालयों में कुल 96.96 लाख शिक्षक हैं। यह 2019-20 में शिक्षकों की संख्या की तुलना में लगभग 8800 अधिक है।
- 2020-21 में **छात्र शिक्षक अनुपात (PTR)** प्राथमिक के लिए 26, उच्च प्राथमिक के लिए 19, माध्यमिक के लिए 18 और उच्च माध्यमिक के लिए 26 था। इसमें 2018-19 से सुधार दिख रहा है। 2018-19 के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए PTR क्रमशः 28, 20, 21 और 30 था।
- 2020-21 में 12.2 करोड़ से अधिक लड़कियों ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक में नामांकन कराया है। इससे 2019-20 में लड़कियों के नामांकन की तुलना में 2020-21 में लड़कियों की संख्या में 11.8 लाख की बढ़ोतरी हुई है।

स्रोत: PIB

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में **WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (WHO GCTM)** की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- आयुष मंत्रालय के तहत WHO GCTM की स्थापना की जाएगी।
- यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम और एकमात्र आउटपोस्टिड वैश्विक केंद्र (कार्यालय) होगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनोम घेबेरियस ने 13 नवंबर, 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भारत में WHO GCTM की स्थापना की घोषणा की थी।
- इस केंद्र की स्थापना के लिए गतिविधियों के समन्वय, निष्पादन और निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य बल (JTF) का गठन किया गया है।
- JTF में भारत सरकार, भारत के स्थायी मिशन, जिनेवा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में तथ्य:

- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **स्थापना:** 7 अप्रैल 1948
- जनवरी 2021 तक, WHO के 194 सदस्य देश हैं।

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त भूमि मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम गठित करने की मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)** को केन्द्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में गठित करने की मंजूरी दी है, जिसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रुपये और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये होगी।

प्रमुख बिंदु

- NLMC केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के स्वामित्व की अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी।
- यह प्रस्ताव बजट 2021-22 की घोषणाओं के अनुरूप है।
- गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी।
- ऐसे CPSE जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में हैं या बंद होने के कगार पर हैं, इन अतिरिक्त भूमि और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण उनके मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: ET

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह की धातुएं (PGM), एंडेलूसाइट, सिलिमाइट और मॉलिबडेनम जैसे कुछ खनिजों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की दर को स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 (इसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस मंजूरी से ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह की धातुओं, एंडेलूसाइट, सिलिमाइट और मॉलिबडेनम के सम्बन्ध में खनिज ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित होगी, जिसके परिणामस्वरूप इन खनिजों के आयात में कमी आयेगी, खनन सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निर्माण सेक्टर, समाज के सबसे बड़े वर्ग के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।
- खान मंत्रालय इन खनिजों के औसत बिक्री मूल्य (ASP) की गणना की पद्धति प्रदान करेगी, जो इन खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने के लिये जरूरी है।
- वर्ष 2021 में किये गये सुधारों से इसे और गति मिली तथा, वित्त वर्ष 2021-22 में 146 से अधिक ब्लॉकों को रखा गया। वित्त वर्ष के दौरान इनमें से 34 ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने NEET-UG परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने NEET-UG परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस आशय के लिए स्नातक चिकित्सा शिक्षा 1997 पर नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

- इससे पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष थी।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश में चिकित्सा शिक्षा का शीर्ष नियामक निकाय है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या NEET (UG) के बारे में:

- NEET (UG), पूर्व में ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT), उन छात्रों के लिए एक अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जो अंडरग्रेजुएट मेडिकल (MBBS), डेंटल (BDS) और आयुष (BAMS, BUMS, BHMS, आदि) पाठ्यक्रम करना चाहते हैं।
- यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाती है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पूसा कृषि विज्ञान मेला- 2022 का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर, श्री चौधरी ने दो एकड़ क्षेत्र में विकसित "पूसा एग्री कृषि हाट परिसर" राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- तीन दिवसीय कृषि मेला का आयोजन ICAR -भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा किया जा रहा है।
- किसान और किसान उत्पादक संगठन 'पूसा एग्री कृषि हाट परिसर' में अपने उत्पादों का सीधा विपणन कर सकेंगे।
- इस सुविधा से उपभोक्ता सीधे किसानों के उत्पाद खरीद सकेंगे, जिससे उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।

स्रोत: PIB

ब्रह्मपुत्र (NW2) का गंगा (NW1) से जुड़ाव

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय पत्तन, नौवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में पटना से बांग्लादेश होते हुए पांडु तक खाद्यान्न की पहली जलयात्रा का स्वागत किया।

प्रमुख बिंदु

- असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) गंगा (NW1)** और **ब्रह्मपुत्र (NW2)** के बीच एक निर्धारित अनुसूचित नौकायन की योजना बना रहा है।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत बांग्लादेश के रास्ते ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को फिर से जीवंत करने के निरंतर प्रयास को प्रोत्साहन मिला है।
- प्रधानमंत्री की "एक्ट ईस्ट" नीति के अनुरूप, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के माध्यम से **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW1)**, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और NW2 पर कई आधारभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाएं शुरू की हैं।
- इन कदमों से जलमार्गों के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के साथ संपर्क में सुधार होगा।
- सरकार ने 2,000 टन तक के जहाजों की सुरक्षित और सतत आवाजाही के लिए NW-1 (गंगा नदी) की क्षमता वृद्धि को लेकर लगभग 4,600 करोड़ रुपये के निवेश के साथ महत्वाकांक्षी **जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP)** शुरू की है।

नोट:

- भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं जिनमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) घोषित किया गया है।
- NW-1: गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (प्रयागराज-हल्दिया) 1620 किमी लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है।
- अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करने के लिए भी अनुमोदित किया गया था।

स्रोत: PIB

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव' अभियान का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने शिक्षा मंत्रालय और UNICEF के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा/या कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिये एक अभूतपूर्व अभियान **'कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव'** का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- स्कूल में 11-14 साल की उम्र की लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों के लिए एक व्यापक प्रणाली पर काम करने के लिए मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे किशोरियों के लिये योजना (SAG), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) पर निर्माण करना है।
- अभियान की शुरूआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत की जायेगी। इसका लक्ष्य है स्कूल छोड़ने वाली चार लाख से अधिक किशोरियों को योजनाओं का लाभ देना है।

UNICEF के बारे में:

- UNICEF, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
- स्थापना: 11 दिसंबर 1946

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - "समर्थ"

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - **"समर्थ"** का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

MSME मंत्रालय की समर्थ पहल के अंतर्गत, इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे:

- मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित **मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों** में **20 प्रतिशत** सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। इससे **7500 से अधिक महिलाएं** लाभान्वित होंगी।
- मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिए योजनाओं के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए **MSME व्यापार प्रतिनिधिमंडल** का **20 प्रतिशत** हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME को समर्पित होगा।
- **NSIC की वाणिज्यिक योजनाओं** पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर **20 प्रतिशत** की छूट।
- **उद्यम पंजीकरण** के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME के पंजीकरण के लिए **विशेष अभियान**

नोट: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है, यह 2021 में 156 देशों में 140वें स्थान पर है।

महिलाओं से सम्बंधित वैधानिक ढाँचा:

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

स्रोत: PIB

NIESBUD ने स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) के अधीन स्वायत्तशासी संगठन **राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD)** ने **स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (SVEP)** पहल के जरिये मैदानी स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिये एक सतत स्वरूप विकसित करने के वास्ते ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- SVEP, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित होने वाले दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का उप-घटक है।
- इसका उद्देश्य गैर-कृषि सेक्टर में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिये ग्रामीण इलाकों के उद्यमियों का समर्थन करना है।
- साझेदारी के तहत ग्रामीण उद्यमी मुद्रा बैंक से समर्थन सहित अपने उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- परियोजना के लाभार्थी DAY-NRLM के स्वयं सहायता समूह (SHG) पारिस्थितिकी तंत्र से हैं और यह योजना न केवल मौजूदा उद्यमों बल्कि नए उद्यमों का भी समर्थन करती है।

स्रोत: ET

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान प्रदान किये

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (VRP), राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (NSA) और प्रतियोगिता वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) [NSA (खान)] प्रदान किए।

प्रमुख बिंदु

- श्रम और रोजगार मंत्रालय, 1965 से "विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (VRP)" और "राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (NSA)" और 1983 से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) [NSA (खान)] का संचालन कर रहा है।
- VRP और NSA का संचालन महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (DGFASLI), मुंबई द्वारा किया जाता है और NSA (खान) का संचालन खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS), धनबाद द्वारा किया जाता है।

स्रोत: PIB

सरकार ने डोनेट-ए-पेंशन कार्यक्रम शुरू किया

चर्चा में क्यों?

- श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने **डोनेट-ए-पेंशन कार्यक्रम** की शुरुआत की।
- यह **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)** पेंशन योजना के तहत एक पहल है, जहां भारत के नागरिक अपने घर या प्रतिष्ठान में अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों ड्राइवरों, हेल्परों, देखरेख करने वालों, नर्सों के लिए प्रमुखता से योगदान कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आयु के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 से 2400 रुपये जमा कराए जा सकते हैं।
- 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन धारकों को प्रति माह तीन हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन की राशि मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) पेंशन योजना के बारे में:

- सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) नामक एक पेंशन योजना शुरू की है।
- PM-SYM श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

असंगठित क्षेत्र के लिए अन्य सरकारी योजनाएं:

- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)
- PM स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम
- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
- आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

ECI ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 की मेजबानी की

चर्चा में क्यों?

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने लगभग 32 देशों के चुनाव प्रबंधन संगठनों (EMB) के लिए **इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IEVP) 2022** की वर्चुअल माध्यम से मेजबानी की।
- ऑनलाइन भाग ले रहे 150 से ज्यादा EMB प्रतिनिधियों के सामने वर्तमान में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनावों का एक सामान्य खाका प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- भारत 2012 के चुनावों से ही इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IEVP) की मेजबानी कर रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें मौजूदा चुनावी प्रक्रियाओं से व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाता है।

ECI (भारतीय निर्वाचन आयोग) के बारे में:

- यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है।
- **स्थापना:** 25 जनवरी 1950 (बाद में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया)
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **आयोग के अधिकारी:**

सुशील चंद्रा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त

राजीव कुमार, भारत के चुनाव आयुक्त

अनूप चंद्र पांडे, भारत के चुनाव आयुक्त

स्रोत: PIB

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (SSSY)

चर्चा में क्यों?

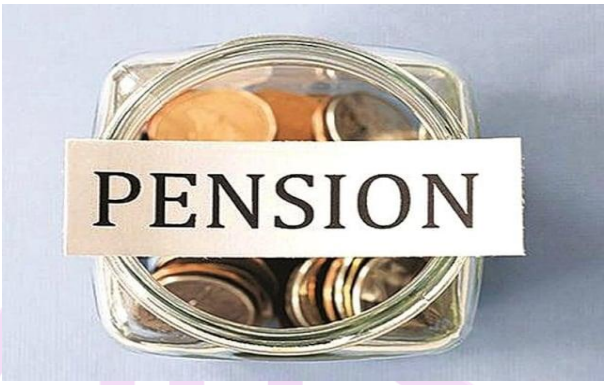

- सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए **स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (SSSY)** और इसके घटकों को 31.03.2021 से आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कुल वित्तीय परिव्यय 3,274.87 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- SSSY को जारी रखने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ था।
- यह निर्णय आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि:

- स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की स्वीकृति दी गई है और वर्तमान में, इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

'सागर परिक्रमा' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा गुजरात सरकार के मत्स्यपालन विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड और मछुआरों के विभिन्न प्रतिनिधियों के सहयोग से **'सागर परिक्रमा'** का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में गुजरात के मांडवी स्थित श्यामीजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू होने वाली यह परिक्रमा तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने का एक प्रयास है।
- इस परिक्रमा को चरणबद्ध रूप से गुजरात के अन्य जिलों और देश के अन्य राज्यों / केन्द्र - शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
- इस आयोजन के दौरान प्रगतिशील मछुआरों, विशेष रूप से तटीय मछुआरों, मछुआरों और मत्स्यपालन से जुड़े किसानों, युवा मत्स्य उद्यमियों आदि को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), किसान क्रेडिट कार्ड और राज्य योजना से संबंधित प्रमाण पत्र / मंजूरी प्रदान की जाएगी।

भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र:

- भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है।
- भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।

मत्स्यपालन से संबंधित पहलें:

- समुद्री शैवाल पार्क
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- पाक खाड़ी योजना
- समुद्री मात्स्यिकी विधेयक

- मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- किसान क्रेडिट कार्ड

स्रोत: PIB

केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV योजना को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के लिए आधुनिकीकरण योजना- III के बाद CAPF के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV को मंजूरी दे दी है।
- यह योजना 1.02.2022 से 31.03.2026 तक लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- CAPF के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV गृह मंत्रालय द्वारा कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू की जानी है।
- इससे CAPF की विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती को ध्यान में रखते हुए, उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार अत्याधुनिक हथियार और उपकरण से लैस किया जाएगा।
- यह अंतरराष्ट्रीय सीमा/LoC/LAC के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेशों, लद्दाख और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की क्षमता को मजबूत करेगा।

स्रोत: इंडिया टुडे

State

भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया

चर्चा में क्यों?

- हैदराबाद में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क, का उद्घाटन किया गया, जिसे तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में, **FICCI लेडीज ऑर्गनाइजेशन (FLO)** द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- 250 करोड़ रुपये के निवेश के साथ बनाया गया 50 एकड़ का FLO औद्योगिक पार्क फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला है, जिसमें चैप्टर सदस्यों के साथ-साथ FLO राष्ट्रीय सदस्यों के लिए भागीदारी है।
- पार्क 16 ग्रीन श्रेणी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संचालित इकाइयों द्वारा 25 महिलाओं के स्वामित्व से परिचालित हो गया।

FICCI लेडीज ऑर्गनाइजेशन (FLO) के बारे में:

- FLO की स्थापना 1983 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के एक डिवीजन के रूप में की गई थी, जो भारत में उद्योग और वाणिज्य का शीर्ष निकाय है।
- महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में, FLO के पूरे भारत में 18 चैप्टर हैं - नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय के साथ अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, लुधियाना, मुंबई, पूर्वोत्तर, पुणे, अमृतसर, पूर्वोत्तर और उत्तराखंड।

स्रोत: इंडिया टुडे

Economy

RBI ने UPI123Pay लॉन्च किया जो फीचर फोन पर UPI भुगतान की अनुमति देता है

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** सेवा लॉन्च की।
- **UPI123Pay** रूप में, यह सेवा पूरे भारत में 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को भुगतान सेवा तक पहुंचने की अनुमति देगी।
- इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक ने डिजीसाथी नामक डिजिटल भुगतान के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू की।

प्रमुख बिंदु

- अभी तक UPI केवल भारत में सभी स्मार्टफोन में उपलब्ध था, लेकिन नवीनतम कदम के साथ, फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को भी भुगतान भेजने और प्राप्त करने की अनुमति होगी।
- UPI123Pay सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को शुरू करने और निष्पादित करने के लिए एक तीन-चरणीय विधि है, जो उन फोन पर काम करेगी जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन का विकल्प नहीं है।

नोट:

- UPI ने फरवरी 2022 में 8.26 लाख करोड़ रुपये के 453 करोड़ लेनदेन दर्ज किए, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग दोगुना है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बारे में:

- UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक तत्काल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो अंतर-बैंक सहकर्मी से सहकर्मी और व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है। NPCI सभी डिजिटल भुगतानों के लिए एक छत्र संगठन है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Defense

भारत - श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नौवां संस्करण 'SLINEX' 2022

चर्चा में क्यों?

- **भारत - श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नौवां संस्करण 'SLINEX' (श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास)** 07 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 तक विशाखापत्तनम में निर्धारित है।
- यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है: 07 मार्च - 08 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण और उसके बाद 09 मार्च -10 मार्च 2022 को बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण।

प्रमुख बिंदु

- श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत SLNS सयूराला और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किर्च, जोकि निर्देशित मिसाइल से लैस एक युद्धपोत है, द्वारा किया जाएगा।
- SLINEX का पिछला संस्करण अक्टूबर 2020 में त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया था।
- SLINEX का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर करना और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है।
- SLINEX भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री मामले में गहरे संबंधों का परिचायक है और पिछले कुछ वर्षों में भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति और 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर)' के दृष्टिकोण के अनुरूप इस दिशा में आपसी सहयोग को मजबूत करने का दायरा बढ़ा है।

स्रोत: PIB

इंडो-पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज (भारत-प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय) सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 07 मार्च, 2022 को चार दिवसीय **इंडो-पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज (IPMHE) सम्मेलन** का उद्घाटन किया। इसकी सह मेजबानी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) और US-इंडो पैसिफिक कमांड (USINDOPACOM) द्वारा की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- सम्मेलन का **विषय** "एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (VUCA) दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य सेवा" है।
- सम्मेलन 10 मार्च, 2022 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सैन्य चिकित्सा में सहयोग और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है।
- इसमें ऑपरेशनल/कॉम्बैट मेडिकल केयर, ट्रॉपिकल मेडिसिन, फील्ड सर्जरी, फील्ड एनेस्थीसिया, एविएशन और मरीन मेडिसिन इमरजेंसी आदि सहित कई महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे।

स्रोत: PIB

भारतीय नौसेना ने लंबी रेंज की जमीन पर हमला करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लंबी दूरी तक जमीन पर सटीक हमले का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

प्रमुख बिंदु

- ब्रह्मोस मिसाइल और INS चेन्नई दोनों का देश में ही निर्माण हुआ और इन्होंने अत्याधुनिक भारतीय मिसाइल तथा जहाज निर्माण कौशल का प्रदर्शन किया।

- इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहलों में भारतीय नौसेना के योगदान को मजबूती मिलती है।
- **ब्रह्मोस एयरोस्पेस**, एक भारत-रूस संयुक्त उद्यम, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।

स्रोत: ET

डिफेंस एक्सपो 2022 स्थगित

चर्चा में क्यों?

- प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की जा रही लॉजिस्टिक्स समस्याओं के कारण गुजरात के गांधीनगर में 10 मार्च से 14 मार्च, 2022 तक आयोजित किया जाने वाला डिफेंस एक्सपो 2022 (12वां संस्करण) स्थगित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- डिफेंस एक्सपो 2022 में भाग लेने वाले 70 देशों में रूस और यूक्रेन शामिल थे।
- डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण 2020 में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित किया गया था।
- डिफेंस एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें भूमि, नौसेना, वायु के साथ-साथ मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है।
- डिफेंस एक्सपो 1996 में शुरू हुआ था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Appointments/Resignations

यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए

चर्चा में क्यों?

- दक्षिण कोरिया में विपक्ष के उम्मीदवार और एक रूढ़िवादी पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- यून सुक योल ने सत्ताधारी उदारवादी पार्टी के प्रतिद्वंदी ली जे मायुंग को हराया।
- यून मई में अपना कार्यभार संभालेंगे और विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में पांच वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहेंगे।

स्रोत: TOI

Important Days

8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का **विषय** 'एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता' है।
- पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह वर्ष 1911 में हुआ था।

नोट:

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द वर्ष 2020 और 2021 के लिये 29 हस्तियों को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे।
- **'नारी शक्ति पुरस्कार'** व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किये जाने वाले उत्कृष्ट योगदानों को मान्यतास्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किये जाते हैं। ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिये जाते हैं, जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महती कार्य किया हो।

स्रोत: un.org

Science & Technology

वैज्ञानिकों ने यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन के उत्पादन को विकसित किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली (इलेक्ट्रोकैटलिस्ट सिस्टम) को तैयार किया है।

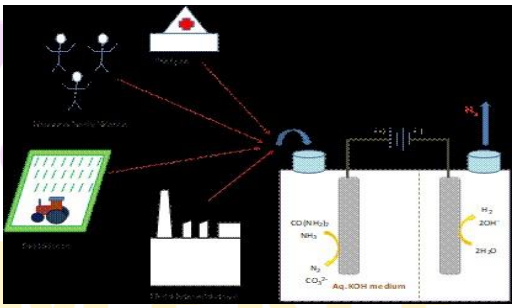

प्रमुख बिंदु

- यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक है।
- भारत यूरिया उत्पादन में शीर्ष देशों में से एक है, और इसने 2019-20 के दौरान 244.55 LMT यूरिया का उत्पादन किया।
- नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक उद्योग अपशिष्ट के रूप में अमोनिया और यूरिया की उच्च सांद्रता का उत्पादन करते हैं।
- इसका उपयोग हमारे देश के लाभ के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
- यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जल के विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) के माध्यम से होने वाले हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को 70% तक कम किया जा सकता है।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में पेटास्केल सुपरकंप्यूटर ''परम गंगा'' स्थापित किया गया

चर्चा में क्यों?

- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)** ने 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ IIT रुड़की में एक सुपरकंप्यूटर **''परम गंगा''** की तैनाती की है।
- यह प्रणाली NSM की चरण-2 की निर्माण पहुंच के तहत C-DAC द्वारा डिजाइन और चालू की गई है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के बारे में:

- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM), जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ने काफी प्रगति की है।
- NSM के चार प्रमुख स्तम्भ हैं जिनके नाम बुनियादी ढांचा, अनुप्रयोग, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास हैं। ये स्तम्भ देश के स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।
- इस मिशन की निर्माण पहुंच के तहत डिजाइन, विकास, सुपरकंप्यूटिंग प्रणालियों की तैनाती और कार्य करने की जिम्मेदारी C-DAC को सौंपी गई है।
- इसने कंप्यूटर सर्वर ''रुद्र'' और उच्च गति वाले इंटरकनेक्ट ''त्रिनेत्र'' को डिजाइन और विकसित किया है, जो सुपर कंप्यूटरों के लिए आवश्यक प्रमुख उप-असेंबलियां हैं।

स्रोत: PIB

हंसा-NG ने पुद्दुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा-NG ने पुद्दुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- हंसा-NG को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में बंगलुरु स्थित CSIR-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (NAL) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- हंसा-NG जस्ट-इन-टाइम प्रीप्रेग (JIPREG) कम्पोजिट लाइट वेट एयरफ्रेम, ग्लास कॉकपिट, व्यापक पैनोरमिक व्यू के साथ बबल कैनोपी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फ्लैप आदि जैसी अनूठी विशेषताओं के साथ रोटैक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन द्वारा संचालित सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर में से एक है।
- हंसा-NG को भारतीय फ्लाइंग क्लब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कम लागत तथा कम ईंधन खपत के कारण वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग (CPL) के लिए एक आदर्श विमान है।

नोट: हंसा-NG (हंसा-नई पीढ़ी) हंसा का एक उन्नत संस्करण है, जिसने 1993 में पहली उड़ान देखी थी और 2000 में प्रमाणित किया गया था।

स्रोत: PIB

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच प्रणाली के परीक्षण का निरीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में लिंगमपल्ली-विकाराबाद खंड पर गुल्लागुडा-चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच **'कवच'** कार्य प्रणाली के परीक्षण का निरीक्षण किया।
- आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में, 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

कवच के बारे में:

- कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित ATP प्रणाली है और भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा के सम्मिलित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने इसका परीक्षण किया है।
- यह सम्पूर्ण सुरक्षा स्तर-4 मानकों की एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है।
- कवच ट्रेनों को खतरे (लाल) पर सिग्नल पार करने और टक्कर रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।
- यदि चालक गति सीमा के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करता है।

रेलवे से संबंधित अन्य पहलें:

- पारगमन उन्मुख विकास
- ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम
- राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान
- रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

नवीनतम डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलोजी में भारत का पहला स्टार्ट-अप

चर्चा में क्यों?

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ऊर्जा दक्षता के निर्माण को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम **डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलोजी** में एक अद्वितीय स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलोजी के लिए भारत में एकमात्र स्टार्ट-अप कंपनी 'स्काईशेड डेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड' हैदराबाद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वैधानिक निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- कंपनी का लक्ष्य हरित और नेट जीरो भवन बनाना तथा जलवायु परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत राष्ट्रीय मिशनों में भाग लेना और योगदान करना है।

नोट:

- देश ने 2022 के आखिर तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा आवश्यकता के 175 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और 2030 तक 500 गीगावाट प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में कहा था।

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें:

- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता
- प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना
- मानक और लेबलिंग
- मांग पक्ष प्रबंधन
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
- ECO निवास संहिता

स्रोत: PIB

Environment

दक्षिणी पश्चिमी घाटों में खोजी गई जिन बेरी की नई प्रजातियां

चर्चा में क्यों?

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य से एक नई जिन बेरी प्रजाति की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- एक विशिष्ट बड़े सफेद फल के साथ ग्लाइकोस्मिस एल्बीकार्पा नाम की प्रजाति, दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है।
- यह प्रजाति ऑरेंज परिवार, रूटासी से संबंधित है।

- निष्कर्ष स्वीडन से प्रकाशित नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी के नवीनतम अंक में प्रकाशित किए गए हैं।
- इन टैक्सोनॉमिक समूहों के कई संबंधित पौधों का उपयोग उनके औषधीय मूल्यों और भोजन के लिए किया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू

Sports

एस श्रीसंत ने भारतीय घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

- विश्व कप विजेता भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 वनडे खेले, जिसमें उन्होंने क्रमश: 87 और 75 विकेट लिए। उन्होंने 10 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सात विकेट भी लिए हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

ISSF WC 2022: 4 स्वर्ण, 2 रजत, एक कांस्य के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर

चर्चा में क्यों?

- भारत ने काहिरा में **अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (ISSF) विश्व कप 2022** में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय टीम चार स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य सहित कुल सात पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही।
- प्रतियोगिता में नॉर्वे दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

मिताली राज छह विश्व कप में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं

चर्चा में क्यों?

- भारत की कप्तान मिताली राज प्रतिष्ठित सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तानी महान जावेद मियांदाद के साथ छह विश्व कप में भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला बनीं।

प्रमुख बिंदु

- कई यादगार मैचों की 39 वर्षीय अनुभवी राज ने 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 में प्रतियोगिता खेलने से पहले 2000 में विश्व कप में अपना पहला प्रदर्शन किया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जमशेदपुर FC ने ATK मोहन बागान को हराकर पहला ISL विनर शील्ड जीता

चर्चा में क्यों?

- जमशेदपुर FC ने गोवा के पीजेएन स्टेडियम में ATK मोहन बागान पर 1-0 से जीत के बाद अपना पहला इंडियन सुपर लीग (ISL) विनर शील्ड जीता।

प्रमुख बिंदु

- जमशेदपुर FC जमशेदपुर में स्थित एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब है।

इंडियन सुपर लीग (ISL) के बारे में:

- इंडियन सुपर लीग भारतीय फुटबॉल प्रणाली में पुरुषों की पेशेवर शीर्ष स्तरीय फुटबॉल लीग है।
- यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और उनके वाणिज्यिक भागीदारों फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाता है।
- हीरो मोटोकॉर्प के साथ प्रायोजन संबंधों के लिए, इसे आधिकारिक तौर पर हीरो इंडियन सुपर लीग कहा जाता है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

Important Personality

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का निधन

- पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा नामित किए जाने के बाद तरार ने 1997 और 2001 के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।
- तरार ने 1991 से 1994 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था।

स्रोत: इंडिया टुडे

पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिग्स का निधन

- जनरल (सेवानिवृत्त) सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिग्स, जिन्होंने 1990 और 1993 के बीच भारतीय सेना का नेतृत्व किया और 2004 से 2010 के बीच पंजाब के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, का निधन हो गया।
- सेना में अपनी 40 से अधिक वर्षों की शानदार सेवा के अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में दो कार्यकालों की सेवा की थी।

स्रोत: ET

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वार्न का निधन

- पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाजी के दिग्गज शेन वार्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वॉर्न को 1992 और 2007 के बीच 15 साल के करियर में उनकी अद्वितीय उपलब्धियों के लिए विजडन के पांच क्रिकेटरों में से एक के रूप में नामित किया गया था।
- 2013 में, जिस वर्ष उन्होंने पूरी तरह से खेल से संन्यास ले लिया, उन्हें ICC हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस